रणजीत टाइम्स

इंदौर

गुरुवार, 11 जून, 2026

वर्ष 02 | अंक 141 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

यशवंत क्लब के चुनाव 28 जून को होंगे, नामांकन

प्रक्रिया शुरू; मैनेजिंग कमेटी के 9 पदों पर होगा मतदान

शहर के प्रतिष्ठित Yeshwant Club की मैनेजिंग कमेटी के चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जारी सूचना के अनुसार क्लब की प्रबंध समिति के नौ पदों के लिए 28 जून को मतदान कराया जाएगा।

इंदौर। चुनाव की घोषणा के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। क्लब प्रबंधन द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवारों के लिए नामांकन फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। नामांकन पत्र जमा करने, उनकी जांच और अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूरी की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस चुनाव में करीब पांच हजार सदस्य मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान और मतगणना दोनों की प्रक्रिया 28 जून को ही संपन्न कराए जाने की तैयारी है। चुनाव को लेकर क्लब सदस्यों के बीच उत्साह का माहौल है और विभिन्न पदों के लिए संभावित उम्मीदवारों ने संपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। यशवंत क्लब इंदौर का सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थान माना जाता है। ऐसे में क्लब की मैनेजिंग कमेटी के चुनावों पर सदस्यों के साथ-साथ शहर के सामाजिक और व्यावसायिक वर्ग की भी नजर बनी हुई है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद अब क्लब की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में विभिन्न उम्मीदवारों और पैनलों के बीच समर्थन जुटाने की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। 28 जून को होने वाला मतदान यह तय करेगा कि अगले कार्यकाल में क्लब की कमान किन हाथों में होगी।

रूस को कमजोर करने का यूरोप का बड़ा प्लान तैयार, भारत सहित इन देशों की 50 कंपनियों को भी होगा नुकसान

ब्रुसेल्स/नई दिल्ली। रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति के तहत ने नए प्रतिबंधों का खाका तैयार किया है। प्रस्तावित प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस की युद्ध क्षमता और आर्थिक गतिविधियों को सीमित करना है, लेकिन इसका असर केवल रूस तक सीमित नहीं रहेगा। भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सहित कई देशों की करीब 50 कंपनियां भी इसकी चपेट में आ सकती हैं। यूरोपीय संघ का आरोप है कि ये कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस को ऐसे उत्पाद, तकनीक या उपकरण उपलब्ध करा रही हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक और रणनीतिक क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसी वजह से इन कंपनियों को प्रतिबंध सूची में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

यदि ये प्रतिबंध लागू होते हैं तो प्रभावित भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय तकनीक, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य उच्च-स्तरीय औद्योगिक उत्पादों तक पहुंच कठिन हो सकती है। इससे कुछ क्षेत्रों में व्यापारिक लागत बढ़ने और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोप के इस कदम का असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ सकता है। भारत और यूरोपीय देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को देखते हुए भारतीय कंपनियां वैकल्पिक बाजारों और आपूर्ति स्रोतों की तलाश कर सकती हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिबंधों की अंतिम सूची में कौन-कौन सी कंपनियां शामिल होंगी। रूस और पश्चिमी देशों के बीच जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच यूरोपीय संघ लगातार नए आर्थिक प्रतिबंधों पर काम कर रहा है। इन उपायों का उद्देश्य रूस की आय के स्रोतों और तकनीकी पहुंच को सीमित करना बताया जा रहा है।

व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार, यदि भारतीय कंपनियां प्रतिबंधों की जद में आती हैं तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय कारोबार में अतिरिक्त अनुपालन नियमों और नियामकीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं भारत की ओर से अब तक इस प्रस्तावित कदम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर, यूरोपीय संघ के प्रस्तावित प्रतिबंध रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा हैं, लेकिन इनके प्रभाव की आंच भारत समेत कई देशों के कारोबारी समूहों तक पहुंच सकती है।

ममता बनर्जी को बड़ा झटका!

राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव के इस्तीफेसे टीएमसी में बढ़ी हलचल

कोलकाता/गुवाहाटी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख Mamata Banerjee को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी की राज्यसभा सांसद Sushmita Dev ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद उनकी Himanta Biswa Sarma से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर तेज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, सुष्मिता देव के इस्तीफे को टीएमसी के भीतर चल रहे असंतोष और संगठनात्मक खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी के अंदर पिछले कुछ समय से नेतृत्व और रणनीति को लेकर मतभेदों की चर्चाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा टीएमसी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात ने इस घटनाक्रम को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। हालांकि अभी तक सुष्मिता देव की ओर से किसी नई राजनीतिक पारी को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उनकी अगली रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। टीएमसी नेतृत्व ने फिलहाल इस घटनाक्रम पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। पार्टी का कहना है कि संगठन मजबूत है और किसी एक नेता के जाने से उसकी राजनीतिक ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं विपक्ष इसे टीएमसी में बढ़ती अंदरूनी असहमति का संकेत बता रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में टीएमसी के अन्य नेता भी असंतोष खुलकर सामने लाते हैं, तो इसका असर पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति और आगामी चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है। फिलहाल सबकी निगाहें सुष्मिता देव के अगले कदम पर टिकी हैं। उनका इस्तीफा और हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात बंगाल की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है।

राजगढ़ पुलिस थाना कि बड़ी कार्रवाई 70 हजार रुपए कि लुट करने वाले दो आरोपीयों को किया गिरफ्तार

दिलीप पाटीदार

राजगढ़। राजगढ़ पुलिस को लूट के एक मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 70 हजार रुपये की लूट की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस ने मोबाइल फोन एवं फरियादी के दस्तावेज बरामद हुए । पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धार

श्री सचिन शर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पारुल बेलापुरकर एवं अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर श्री विश्वदीप सिंह परिहार के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी राजगढ़ समीर पाटीदार के नेतृत्व में कि गई। थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 मई को फरियादी राजवीर मालवी के साथ लूट की घटना हुई थी। आरोपियों ने उनसे 70 हजार रुपये नकद, मोबाइल फोन तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज छीन लिए थे। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर राजगढ़ थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने मुकेश पिता धुंधरा उम्र 30 साल निवासी काली देवी थाना टांडा जिला धार बबलू उर्फ़ बाबू पिता वीरसिंह उम्र 20 साल निवासी काली देवी थाना टांडाजिला धार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपीयों के कब्जे से फरियादी के मोबाइल फोन आधार कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं 16000 हजार रुपए नकद बरामद किए। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपीयों जांच में आरोपी मुकेश के खिलाफ पूर्व से भी कई गंभीर अपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी मुकेश थाना राजगढ़ के तीन अपराध में पूर्व से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे उन प्रकरणों में भी गिरफ्तार

कर लिया है। मामले में दो आरोपी जालम सिंह और नेहरू अभी भी फरार है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक कीर्तन नायक, निहाल सिंह दंडोतिया, सहायक उप निरीक्षक सैयद अहमद, सुनील राजपूत, रईस पठान, प्रधान आरक्षक विपिन कटारा, आरक्षक दिलीप, अंकित, अमर, सुभाष और अमित की सराहनीय भूमिका रही।

प्रेमजाल, ब्लैकमेल और 6 लाख की ठगी का पर्दाफाश: नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पुलिस कि गिरफ्त में

दिलीप पाटीदार

राजगढ़। दिनांक 07 जून 2026 को थाना राजगढ़ में एक गंभीर शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक नाबालिग बालिका को प्रेमजाल में फंसाकर उससे आर्थिक शोषण, ब्लैकमेलिंग एवं छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए

आरोपी कृष्णा पिता महेश शर्मा, निवासी राजगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी कृष्णा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट के माध्यम से नाबालिग बालिका से संपर्क स्थापित किया और धीरे-धीरे उससे मित्रता बढ़ाई। बातचीत के दौरान आरोपी ने बालिका का विश्वास जीतकर उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। इसके बाद उसने दुर्घटना, आर्थिक परेशानी तथा अन्य आवश्यक कार्यों का हवाला देकर समय-समय पर बालिका से रुपये मांगना शुरू कर दिया। जब पीड़िता द्वारा अपने रुपये वापस मांगे गए तो आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की तथा उसे बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी द्वारा इस प्रकार ब्लैकमेल कर लगभग 06 लाख रुपये हड़प लिए गए।

शिकायत के आधार पर थाना राजगढ़ में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 247/2026 धारा 74, 115(2), 308(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। राजगढ़ थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कृष्णा पिता महेश शर्मा निवासी राजगढ़ को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर प्राप्त की गई राशि को अपने एशो आराम में खर्च करना बताया। पुलिस ने कार्रवाई पूरी कर आरोपी को सरदारपुर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

सराहनीय कार्य

उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक जुली अमलियार, प्रधान आरक्षक रैमसिंह बर्डे, आरक्षक सुभाष एवं आरक्षक दिलीप की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।

जीतसिंह भूरिया, अति उत्कृष्ट सेवा पदक से हुए सम्मानित

सलीम हुसैन

झाबुआ पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रामीण रेंज इंदौर मनोज कुमार सिंह, आईपीएस एवं पुलिस

अधीक्षक झाबुआ देवेंद्र पाटीदार,आईपीएस द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय झाबुआ में पदस्थ मुख्य लिपिक जीतसिंह भूरिया को उनकी उत्कृष्ट, सराहनीय एवं समर्पित सेवाओं के लिए अति उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। जीतसिंह भूरिया पुलिस विभाग में अपनी 44 वर्ष की गौरवपूर्ण सेवा पूर्ण करने के उपरांत 30 जून 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। इस अवसर पर दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके लंबे सेवाकाल के दौरान प्रदर्शित कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, ईमानदारी एवं उत्कृष्ट कार्यशैली की सराहना की। अधिकारियों ने कहा कि भूरिया ने अपने सेवाकाल में विभाग के प्रति पूर्ण समर्पण एवं निष्ठा के साथ कार्य करते हुए पुलिस विभाग की गरिमा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका सेवाकाल युवा पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणादायक रहेगा।

सिल्लारपुर में मौत का धमाका!

ब्लास्ट से कांपे घर, फटीं दीवारें, आदिवासी बस्ती की छतें गिरीं; दहशत में ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम

एनएच-27 पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, घंटों थमा यातायात; एसडीएम अनुराग निग्गवाल की समझाइश के बाद खुला जाम'जान बची तो लाखों पाए'-क्रेशर के भयावह ब्लास्ट से बाल-बाल बचे ग्रामीण, न्याय और कार्रवाई की मांग तेज

ग्रामीणों का आरोप-क्रेशर के विस्फोट ने उजाड़ दिए आशियाने, भाजपा जिला अध्यक्ष पर भी लगाए गंभीर आरोप

पत्थरों की बारिश से सहमा सिल्लारपुर, घरों में दरारें और छतें गिरने से मचा हड़कंप सबसे दमदार और अखबारी प्रभाव वाली मुख्य हेडलाइन होगी:"सिल्लारपुर में मौत का धमाका! ब्लास्ट से कांपे घर, फटीं दीवारें, आदिवासी बस्ती की छतें गिरीं; दहशत में ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम।

रणजीत टाइम्स

सोयाबीन से आगे बढ़ रहा मालवा-निमाड़ ब्लूबेरी से सफेद मूसली तक खेती की नई उड़ान

परंपरागत फसलों से हटकर किसान अपना रहे हाई-वैल्यू खेती, बढ़ रही आय और नए अवसर मालवा-निमाड़ क्षेत्र, जिसे लंबे समय से सोयाबीन की खेती के लिए जाना जाता रहा है, अब कृषि के क्षेत्र में नए प्रयोगों और नवाचारों का केंद्र बनता जा रहा है।

किसान पारंपरिक फसलों की सीमित आय से आगे बढ़ते हुए ब्लूबेरी, सफेद मूसली, ड्रैगन फ्रूट, विदेशी सब्जियों और औषधीय फसलों जैसी हाई-वैल्यू खेती की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, बदलते बाजार, बेहतर तकनीक और बढ़ती मांग ने किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित किया है। इसका परिणाम यह है कि कई किसान अब कम क्षेत्रफल में अधिक लाभ देने वाली फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। विशेष रूप से ब्लूबेरी और सफेद मूसली जैसी फसलें किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। सफेद मूसली

की मांग आयुर्वेदिक और औषधीय उद्योग में लगातार बढ़ रही है, जबकि ब्लूबेरी जैसे विदेशी फलों की मांग महानगरों और निर्यात बाजारों में तेजी से बढ़ रही है। इससे किसानों को पारंपरिक फसलों की तुलना में बेहतर कीमत और अधिक मुनाफा मिल रहा है।

कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिक भी किसानों को नई तकनीकों, उन्नत बीजों और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ड्रिप सिंचाई, पॉलीहाउस और जैविक खेती जैसी तकनीकों ने इन फसलों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसानों को बाजार, भंडारण और प्रसंस्करण की बेहतर सुविधाएं मिलें तो मालवा-निमाड़ क्षेत्र देश में उच्च मूल्य वाली कृषि का बड़ा केंद्र बन सकता है। खेती में यह बदलाव न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रहा है, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी नई दिशा दे रहा है। मालवा-निमाड़ के किसानों की यह नई सोच दर्शाती है कि आधुनिक तकनीक, बाजार की समझ और नवाचार के सहारे खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सकता है। अब यह क्षेत्र केवल सोयाबीन बेल्ट के रूप में नहीं, बल्कि कृषि नवाचार के मॉडल के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है।

MP में कॉर्निया की भारी कमी, दो लाख मरीजों को आंखों की रोशनी का इंतजार

मध्य प्रदेश में कॉर्निया प्रत्यारोपण (कॉर्नियल ट्रांसप्लांट) की जरूरत वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके मुकाबले कॉर्निया दान की उपलब्धता बेहद कम है। स्थिति यह है कि प्रदेश में हर वर्ष लगभग 6 हजार कॉर्निया की आवश्यकता होती है, जबकि सालाना केवल

करीब 1,500 कॉर्निया ही उपलब्ध हो पाते हैं। इसके कारण हजारों मरीजों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदेश में करीब दो लाख लोग ऐसे हैं जो कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिबाधित हैं और उन्हें आंखों की रोशनी वापस पाने के लिए कॉर्निया प्रत्यारोपण की जरूरत है। उपलब्धता और मांग के बीच बड़े अंतर के कारण लगभग 75 प्रतिशत मरीजों को वर्षों तक प्रतीक्षा सूची में रहना पड़ता है। नेत्र रोग विशेषज्ञों का कहना है कि कॉर्निया दान के प्रति जागरूकता की कमी इस समस्या का प्रमुख कारण है। अधिकांश लोग मृत्यु के बाद नेत्रदान की प्रक्रिया और उसके महत्व से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। जबकि एक व्यक्ति के नेत्रदान से दो लोगों को नई रोशनी मिल सकती है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समाज में नेत्रदान को लेकर जागरूकता बढ़े और अधिक लोग इसके लिए संकल्प लें, तो हजारों लोगों की जिंदगी में उजाला लाया जा सकता है। इसके लिए सरकारी संस्थानों, सामाजिक संगठनों और चिकित्सा संस्थाओं को मिलकर व्यापक जनजागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे नेत्रदान के लिए आगे आएं और अपने परिजनों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उनका कहना है कि मृत्यु के बाद किया गया नेत्रदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को फिर से दुनिया देखने का अवसर दे सकता है, जो मानवता की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक है।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द

कांग्रेस के सामने संकट, बीजेपी की राह आसान

भोपाल। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी उम्मीदवार Meenakshi Natarajan का नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। आरोप है कि नामांकन के साथ दाखिल शपथ पत्र (एफिडेविट) में एक मामले से जुड़ी जानकारी का पूर्ण खुलासा नहीं किया गया था। नामांकन रद्द होने के बाद राज्यसभा चुनाव का पूरा समीकरण बदल गया है। कांग्रेस जिस सीट पर मुकाबले की तैयारी कर रही थी, वहां अब भाजपा की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है।

भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए दावा किया था कि उम्मीदवार ने तेलंगाना से जुड़े एक मामले का विवरण शपथ पत्र में नहीं दिया। इसके बाद जांच के दौरान रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन निरस्त कर दिया।

कांग्रेस ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। पार्टी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आघात बताते हुए चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। कांग्रेस का कहना है कि जिस मामले को आधार बनाया गया, वह विवादित है और उम्मीदवार को पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। नामांकन खारिज होने का असर कांग्रेस की रणनीति पर भी पड़ा। पार्टी ने संभावित क्रॉस-वोटिंग की आशंका के बीच अपने विधायकों को दूसरे राज्य भेजने की तैयारी की थी, लेकिन घटनाक्रम बदलने के बाद यह योजना भी प्रभावित हुई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस घटनाक्रम से राज्यसभा की तीनों सीटों पर भाजपा की स्थिति और मजबूत हो गई है। वहीं कांग्रेस अब कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में यह मामला अब केवल एक नामांकन रद्द होने तक सीमित नहीं रह गया है।

सहजयोग में निर्विचार समाधि का महत्व

सहजयोग में निर्विचार समाधि को आत्मसाक्षात्कार के बाद प्राप्त होने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अवस्था माना जाता है। यह वह स्थिति है जिसमें साधक विचारों के निरंतर प्रवाह से ऊपर उठकर शुद्ध चेतना और वर्तमान क्षण की जागरूकता में स्थापित हो जाता है। इस अवस्था में मन शांत हो जाता है, किन्तु व्यक्ति पूर्णतः सजग और सचेत रहता है। परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी ने निर्विचार समाधि के विषय में कहा है कि, "विचारों के लुप्त होने का अर्थ है, आप स्वयं में ही विलीन हो गए। यही वास्तविकता है, परन्तु आप जागरूक भी हैं।"(20/10/1996) अर्थात् निर्विचारता कोई अचेतन अवस्था नहीं है, बल्कि यह जागृत चेतना की सर्वोच्च अवस्था है जहाँ साधक वास्तविकता का प्रत्यक्ष अनुभव करता है।

श्री माताजी ने यह भी कहा है कि, "साधक में निर्विचार स्थिति प्राप्त होना उन्नति की पहली सीढ़ी है।"(27/9/1997) सहजयोग के अनुसार जब कुण्डलिनी शक्ति आज्ञा चक्र को पार कर सूक्ष्म क्षेत्र में प्रवेश करती है, तब निर्विचारता स्थापित होने लगती है। यह अवस्था साधक के भीतर शांति, संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति का विकास करती है। श्री माताजी के शब्दों में- "निर्विचार समाधि आपको शान्ति प्रदान करती है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है।" निर्विचारता में रहने से व्यक्ति के भीतर एक गहरा आंतरिक परिवर्तन आता है। समस्याओं के समाधान सहज रूप से प्राप्त होने लगते हैं, मानसिक तनाव कम हो जाता है और दिव्य शक्ति का मार्गदर्शन जीवन में स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगता है। इस प्रकार निर्विचार समाधि सहजयोग की साधना का मूल आधार और आत्मिक उत्कर्ष का द्वार है। सहजयोग केवल ध्यान की एक पद्धति नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित, शांत और आनंदमय बनाने का एक समग्र मार्ग है। नियमित सहजयोग ध्यान से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, करुणा और संतोष का विकास होता है जिससे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होता है। परम पूज्य श्री माताजी ने सिखाया कि सहजयोग का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत कल्याण नहीं, बल्कि मानवता के सामूहिक उत्थान और विश्व शांति की स्थापना भी है। नियमित ध्यान के माध्यम से साधक अपने भीतर की दिव्य शक्ति से जुड़कर अधिक संतुलित, आनंदित और सार्थक जीवन जीने लगता है। सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 अथवा वेबसाइट www.sahajayoga.org.in से प्राप्त कर सकते हैं । सहजयोग पूर्णतया निशुल्क है।

लोकतंत्र की अस्मिता बचाने को कांग्रेस का उपवास सत्याग्रह, करैरा में गूंजा विरोध का स्वर

करैरा। लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के संकल्प के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को करैरा तहसील कार्यालय परिसर में उपवास सत्याग्रह कर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आघात है तथा इससे संविधान की भावना को ठेस पहुंची है।

इस विरोध कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा और जनमत के सम्मान की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास रखा। वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में निहित है तथा किसी भी प्रकार की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रही है और आगे भी जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा को अपना संकल्प बताते हुए कहा कि जनभावनाओं की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उपवास सत्याग्रह में जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम रावत, ब्लॉक अध्यक्ष रूपेंद्र यादव, पूर्व जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष मानसिंह फौजी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष डी.सी. श्रीवास्तव, लाली बैदोरिया, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र भार्गव, राजेंद्र व्याघ्र, धर्मचंद जैन एडवोकेट, बलराम यादव सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने लोकतंत्र, संविधान और जनाधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

राजगढ़ में "गण आपके द्वार" कार्यक्रम संपन्न, धर्म आराधना से जुड़ने का आह्वान

दिलीप पाटीदार

राजगढ़, 10 जून। महावीर स्थानक भवन, राजगढ़ में श्री धर्मदास गण परिषद के "गण आपके द्वार" कार्यक्रम के अंतर्गत तत्वज्ञ पूज्य श्री धर्मेन्द्रमुनिजी म.सा. आदि ठाणा 6 के दर्शन, वंदन एवं मांगलिक श्रवण का लाभ प्राप्त किया गया। मेघनगर एवं झाबुआ श्रीसंघ में प्रवास के पश्चात श्री धर्मदास गण परिषद का दल राजगढ़ पहुंचा।

इस अवसर पर गण के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरतजी भंसाली, महामंत्री शैलेशजी पीपाड़ा, दीपकजी रुणवाल, सोहनलालजी रुणवाल सहित अन्य सदस्य राजगढ़ श्रीसंघ में पधारे, जिनका श्रीसंघ द्वारा बहुमान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष भरतजी भंसाली ने श्रावण एवं भाद्रपद मास में आयोजित होने वाली मिनी वर्षीतप आराधना से अधिकाधिक श्रावक-श्राविकाओं को जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिन साधकों को अनुकूलता हो, वे पूर्ण वर्षीतप आराधना भी सातापूर्वक संपन्न करें।

उन्होंने आगामी वर्षावास 2026 के दौरान श्रावण मास की विशेष आराधनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए संघजनों से घर-घर धर्म संदेश पहुंचाने एवं अधिकाधिक लोगों को आराधना से जोड़ने का आग्रह किया। साथ ही बताया कि 28 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ होने के साथ ही स्थानीय स्वाध्याय संघ के स्वाध्यायी प्रतिदिन अपनी सेवाएं श्रीसंघ को प्रदान करेंगे। गण परिषद द्वारा द्वितीय वर्ष में विशेष सामायिक आराधना के अंतर्गत वर्षभर में 1500 सामायिक तथा पक्खी पर्व की आराधना एवं प्रतिक्रमण करने वाले कुल 24 श्रावक-श्राविकाओं का सम्मान एवं पुरस्कार वितरण भी किया गया।

इस अवसर पर अणु जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आयोजित होने वाली आगामी आराधनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। गण परिषद ने सभी श्रीसंघों को अधिक से अधिक धर्म आराधना से जोड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के सदस्य संतोषजी बुरड़, नरेंद्रजी मूणत, अनिलजी नखेत्रा, वर्धमानजी, ज्ञानचंदजी, सचिनजी, अंकुशजी खाबिया, आशीषजी वागरेचा, पंकजजी, हर्षजी मामा, हितेश वागरेचा सहित अनेक श्रावक-श्राविकाएं उपस्थित रहे। सभी के सहयोग से "गण आपके द्वार" कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह जानकारी संघ के मीडिया प्रभारी हितेश वागरेचा द्वारा प्रदान की गई।

राज्यसभा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर भाजपा ने किया लोकतंत्र पर प्रहार

सलीम हुसैन

कांग्रेस जनों ने 4 घंटे उपवास कर जताया विरोध

झाबुआ । 9 जून को को भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फॉर्म को निरस्त कर प्रजातंत्र पर हमला किया है कांग्रेस ने भाजपा के इस कृत्य का पुर जोर विरोध प्रकट दोपहर 12 से सायं 4 बजे तक 4 घंटे उपवास कर किया ।

इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रांका ने कहां की कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त सरासर लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ है भाजपा एक तरफ नारी सम्मान और महिला सशक्तिकरण के नारे देती है वही दूसरी ओर षड्यंत्र रचकर अपमानित करती है देश प्रदेश की जनता भाजपा की कथनी करनी का अंतर समझ चुकी है आगामी चुनाव में जनता जनार्दन

इन्हें जवाब दे देगी । मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव निर्मल मेहता ने कहा देश के लोकतंत्र में सत्ता की जो भूमिका होती है उसका नाजायज तरीके से उपयोग कर प्रजातंत्र पर हमला है यह लड़ाई नहीं बुजदिली है यह राजनीति नहीं लोकतंत्र का अपहरण है नामांकन फार्म के कालम में अपराधिक लंबीत प्रकरण की जानकारी दी जाती है किसी प्रकार के नोटिस का कोई कालम नहीं रहता भाजपा का यह कृत्य लोकतंत्र संविधान के साथ कुठाराघात जैसा कदम है । इस अवसर पर जिला संगठन मंत्री शंकर सिंह भूरिया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवेल कैलाश डामोर रूप सिंह डामोर जनपद अध्यक्ष ललिता मुकेश मुनिया युवा कांग्रेस अध्यक्ष नटवर डोडियार यामीन शेख एनएसयूआई अध्यक्ष नर्वेश अमलियार सुनीता अलावा आईटी सेल अध्यक्ष वसीम सैयद महामंत्री हर्ष जैन बबलू कटारा कीलु भूरिया गोरी कटारा रमेश मांडली सायरा बानू मारिया वड़किया मालू डोडियार मुकेश मुनिया गुफरान कुरैशी आयुष ओहरी मनोश गुड़िया दीपक मखोडिया अल्केश पारगी सहित कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता उपवास आयोजन में उपस्थित थे उक्त जानकारी जिला कॉंग्रेस प्रवक्ता अली असगर बोहरा द्वारा दी गई हैं ।

दिनांक 10/ 6 /2026 को नगर परिषद आंतरी अध्यक्ष श्रीमती सुनीता सुनील शर्मा जी द्वारा वार्ड क्रमांक 8 में निर्माणअधीन नाले पर निरीक्षण किया एवं गुणवत्ता पूर्ण कार्य किए जाने हेतु ठेकेदार को निर्देशित किया गया ठेकेदार द्वारा यथाशीघ्र कार्य पूर्ण किए जाने हेतु आस्वत किया गया इस दौरान वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद श्री इब्राहिम खान जी श्री मदनपाल कुशवाहा प्रभारी स्टोर कीपर मोनू दुबे मोहन सिंह रजक एवं नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी उपस्थिति रहें।

कलेक्टर की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों एवं अंतर्विभागीय समन्वय बैठक आयोजित

सलीम हुसैन

झाबुआ,। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में समयावधि पत्रों एवं अंतर्विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति, लंबित प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों एवं शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर डॉ. भरसट ने सीएम हेल्पलाइन से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबित शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने तथा ग्रेडिंग मंथ के अंतर्गत शत-प्रतिशत शिकायतों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

कलेक्टर ने सीएम हाउस में लंबित शिकायतों की समीक्षा की। नगर परिषदों को सहरी ड्रेनेज एवं नाला सफाई बारिश के पूर्व करे। "A" मार्क की गई पत्रों की विभागवार समीक्षा की गई। 12 जून से 18 जून 2026 तक जनकल्याण शिविर आयोजित किये जाएंगे। जिसमें 23 विभाग 110 सेवा के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। कलेक्टर ने भू अर्जन, भूमि आवंटन प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेन्द्र सिंह चौहान, अपर कलेक्टर सी.एस. सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद तनुश्री मीणा, संयुक्त कलेक्टर विजय कुमार मंडलोई, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षयसिंह मरकाम, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

“5 लाख पेंशनर्स की पीड़ा पहुंची सरकार तक, लंबित मांगों के निराकरण हेतु सौंपा ज्ञापन”

अतुल जैन

(महंगाई राहत, स्वास्थ्य बीमा, सातवें वेतनमान का एरियर और न्यायालयीन आदेश लागू करने सहित कई मुद्दे उठाए)

खनियाधाना। मध्यप्रदेश के लाखों पेंशनर्स की वर्षों से लंबित मांगों और समस्याओं के निराकरण को लेकर प्रोग्रेस पेंशनर्स एसोसिएशन शाखा खनियाधाना ने मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन नायब तहसीलदार रामनरेश आर्य को सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश के लगभग 5 लाख पेंशनर्स से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.डी. स्वर्णकार के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इससे पेंशनर्स और उनके परिवारों में गहरी निराशा व्याप्त है।

(केंद्र के समान लाभ देने की मांग)

ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स को जहां समय-समय पर महंगाई राहत और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वहीं मध्यप्रदेश के पेंशनर्स को कई लाभों से वंचित रखा जा रहा है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। संगठन ने मांग की कि राज्य के पेंशनर्स को भी केंद्र सरकार की तर्ज पर सभी सुविधाएं एवं आर्थिक लाभ प्रदान किए जाएं।

(स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रीमियम का विरोध)

पेंशनर्स संगठन ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना में पेंशनर्स से 4 प्रतिशत प्रीमियम लिए जाने के प्रावधान पर आपत्ति जताई है। ज्ञापन में कहा गया कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ही उनकी आय का प्रमुख साधन होती है, ऐसे में अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना न्यायसंगत नहीं है। संगठन ने पेंशनर्स से किसी भी प्रकार का प्रीमियम न लेने की मांग की।

(वर्षों तक लटके रहते हैं आर्थिक लाभ)

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पेंशनर्स को मिलने वाले विभिन्न वित्तीय लाभों और एरियर का भुगतान समय पर नहीं किया जाता। कई मामलों में लाभ राशि 4 माह से लेकर 58 माह तक विलंब से मिलती है। संगठन ने कहा कि यह स्थिति पेंशनर्स के अधिकारों का हनन है और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(सातवें वेतनमान का एरियर और बकाया राशि शीघ्र मिले)

पेंशनर्स ने ज्ञापन के माध्यम से सातवें वेतनमान के लंबित एरियर एवं अन्य बकाया भुगतान को तत्काल जारी करने की मांग की। साथ ही कहा कि विलंब से भुगतान होने पर संबंधित राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज भी दिया जाना चाहिए।

(न्यायालय के आदेश लागू करने की मांग)

ज्ञापन में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पेंशनर्स के हित में दिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की गई। संगठन का कहना है कि कई मामलों में न्यायालय के आदेशों के बावजूद पेंशनर्स को उनका वैधानिक लाभ नहीं मिल पा रहा है।

(80 वर्ष के अतिरिक्त लाभ की आयु सीमा में संशोधन की मांग)

पेंशनर्स एसोसिएशन ने मांग की कि वर्तमान में 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मिलने वाला 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ 79 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही प्रदान किया जाए, ताकि वृद्ध पेंशनर्स को समय पर उसका लाभ मिल सके।

(उपदान राशि कर्मचारियों की तरह देने की मांग)

ज्ञापन में कर्मचारियों की भांति पेंशनर्स को भी उपदान (ग्रेच्युटी) राशि का लाभ दिए जाने की मांग की गई। संगठन का कहना है कि यह उनका अधिकार है और इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(समस्याओं के संवेदनशील समाधान की अपील)

ज्ञापन के अंत में मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया कि प्रदेश के लाखों पेंशनर्स की समस्याओं पर मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्र निर्णय लिया जाए। संगठन ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने अपना पूरा जीवन शासन-प्रशासन की सेवा में लगाया, उनके सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। उज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। नायब तहसीलदार रामनरेश आर्य ने ज्ञापन प्राप्त कर इसे शासन स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

छत्तीसगढ़ में घर-घर पहुंचेंगे मंत्री, सांसद और विधायक, जनता से सीधे संवाद करेंगे नेता

मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा का प्रदेशव्यापी ‘घर-घर चलो अभियान’ शुरू केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में व्यापक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। ‘घर-घर चलो अभियान’ के तहत मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारी सीधे लोगों के घर पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे तथा जनता से फीडबैक भी लेंगे।

भाजपा के इस अभियान का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना और आम लोगों की समस्याओं व सुझावों को सीधे सुनना बताया जा रहा है। अभियान के दौरान जनप्रतिनिधि विभिन्न क्षेत्रों में घर-घर जाकर नागरिकों से संवाद करेंगे और सरकार की योजनाओं के प्रभाव का आकलन करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करेंगे और किसी भी क्षेत्र में आम नागरिकों के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं।

इससे सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। भाजपा ने अभियान को बूथ स्तर तक ले जाने की रणनीति बनाई है। कार्यकर्ताओं को घर-घर संपर्क कर केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ब्रिक्स सम्मेलनः कृषि चुनौतियों का समाधान साझेदारी, नवाचार और ज्ञान साझा करने से ही संभव

बदलती जलवायु और खाद्य सुरक्षा पर सदस्य देशों के बीच मंथन, टिकाऊ कृषि मॉडल पर जोर

ब्रिक्स देशों के कृषि कार्य समूह (AWG) सम्मेलन में कृषि क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा हुई। सम्मेलन के पहले दिन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव आतीश चंद्र ने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बदलती जलवायु परिस्थितियों, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने जैसी चुनौतियों का प्रभावी समाधान केवल आपसी सहयोग, नवाचार और ज्ञान के आदान-प्रदान से ही संभव है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों, अनुसंधान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन पर पड़ रहे प्रभाव, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने, आधुनिक तकनीकों के उपयोग तथा खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर विशेष चर्चा हुई। सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने देशों के अनुभव साझा किए और कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। सम्मेलन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कृषि को अधिक लचीला, टिकाऊ और तकनीक-सक्षम बनाने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित

करने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की यह बैठक सदस्य देशों के बीच कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को नई दिशा देने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

ग्रामीण विकास के लिए खुला केंद्र का खजाना! 'वीबी-जी राम जी' प्रोजेक्ट के लिए 95,692 करोड़ की बड़ी घोषणा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ी वित्तीय पहल की घोषणा की है। सरकार ने 'वीबी-जी राम जी' (VBG-RAMG) परियोजना के तहत 95,692 करोड़ रुपये का अंतरिम फंड आवंटित करने का फैसला किया है।

इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी, आवास और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में विकास की गति को तेज करना है, ताकि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। परियोजना के तहत सड़क नेटवर्क को मजबूत करने, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई

ऊर्जा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं के विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न आजीविका कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्र सरकार का मानना है कि सीमावर्ती और दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलित विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इन इलाकों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस फंड का प्रभावी उपयोग किया जाता है, तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, पलायन में कमी आएगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी। सरकार का दावा है कि यह निवेश ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

विधायक-सांसद के बाद अब ऑफिस की बारी, TMC के हाथ से निकल सकता है दिल्ली वाला दफ्तर

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी में जारी अंदरूनी खींचतान अब संगठनात्मक स्तर से आगे बढ़कर संसदीय और प्रशासनिक मोर्चे तक पहुंचती दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष के बीच दिल्ली स्थित टीएमसी कार्यालय पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार, टीएमसी के कई असंतुष्ट सांसदों ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री के आवास पर बैठक की थी। इस बैठक के बाद पार्टी की वरिष्ठ सांसद ने दावा किया कि 20 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ लोकसभा अध्यक्ष को अलग संसदीय समूह के गठन का प्रस्ताव सौंपा गया है। यदि सांसदों का यह दावा स्वीकार किया जाता है, तो संसद में टीएमसी की आधिकारिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संसदीय दल में विभाजन की स्थिति बनने पर दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय और उससे जुड़ी अन्य सुविधाओं पर अधिकार को लेकर भी विवाद खड़ा हो सकता है। हाल के दिनों में टीएमसी के भीतर नेतृत्व और संगठनात्मक फैसलों को लेकर असहमति की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। विधानसभा और लोकसभा दोनों स्तरों पर कुछ नेताओं के बागी रुख ने पार्टी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं। विपक्षी दल भी इस घटनाक्रम को पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं।

हालांकि, टीएमसी नेतृत्व की ओर से अब तक आधिकारिक रूप से किसी बड़े विभाजन को स्वीकार नहीं किया गया है। पार्टी का कहना है कि संगठन एकजुट है और असंतोष की खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम पर नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका असर न केवल संसद में पार्टी की ताकत पर पड़ सकता है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उसकी भूमिका को भी प्रभावित कर सकता है।

मुंबई में 19 हजार से ज्यादा जन्म प्रमाणपत्रों में किए गए बदलाव होंगे रद्द, सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में वर्ष 2024 से 2026 के बीच जन्म प्रमाणपत्रों में किए गए 19,734 संशोधनों को रद्द करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम जन्म प्रमाणपत्रों में कथित अनियमितताओं, फर्जीवाड़े और नियमों के उल्लंघन की आशंकाओं को देखते हुए उठाया गया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान पाया गया कि बड़ी संख्या में जन्म प्रमाणपत्रों में नाम, जन्म तिथि, माता-पिता की जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों में संशोधन किए गए थे। इनमें से कई मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया, जिससे दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए।

महाराष्ट्र सरकार ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे सभी संशोधनों की समीक्षा करने और नियमों के अनुरूप न पाए जाने वाले बदलावों को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जन्म प्रमाणपत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का दुरुपयोग न हो और नागरिक अभिलेखों की प्रामाणिकता बनी रहे। अधिकारियों का कहना है कि जन्म प्रमाणपत्र पहचान, शिक्षा, पासपोर्ट, सरकारी योजनाओं और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए एक अहम दस्तावेज है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अनियमितता राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने वैध कारणों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत संशोधन करवाए हैं, उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ दोबारा आवेदन करने का अवसर दिया जा सकता है। वहीं संदिग्ध मामलों की विस्तृत जांच भी जारी रहेगी। इस फैसले के बाद प्रभावित नागरिकों को अपने दस्तावेजों की स्थिति की जांच करने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। सरकार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और नागरिक रिकॉर्ड प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना है।

भारत ने बढ़ाया परमाणु हथियारों का जखीरा, SIPRI की रिपोर्ट देख पाकिस्तान की बढ़ी चिंता

नई दिल्ली/स्टॉकहोम। वैश्विक सुरक्षा मामलों पर नजर रखने वाली संस्था Stockholm International Peace Research Institute की ताजा रिपोर्ट में भारत की परमाणु क्षमता को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने परमाणु हथियारों के भंडार में बढ़ोतरी की है, जिससे दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास वर्ष 2025 की तुलना में अब अधिक संख्या में परमाणु हथियार हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत लगातार अपनी परमाणु त्रिस्तरीय क्षमता (थल, जल और वायु आधारित परमाणु प्रणाली) को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत लंबी दूरी की मिसाइलों और आधुनिक डिलीवरी सिस्टम पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपने-अपने परमाणु कार्यक्रमों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। हालांकि भारत की रणनीति मुख्य रूप से न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता (Credible Minimum Deterrence) पर आधारित रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की बढ़ती सामरिक क्षमता पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय हो सकती है। पाकिस्तान लंबे समय से अपने परमाणु कार्यक्रम को भारत के संदर्भ में देखता रहा है, ऐसे में भारत के हथियार भंडार और तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के अधिकांश परमाणु हथियार अभी भी Russia और United States के पास हैं, लेकिन एशिया में भारत, पाकिस्तान और China के परमाणु कार्यक्रमों पर भी वैश्विक निगाहें बनी हुई हैं। विश्लेषकों का कहना है कि बदलते भू-राजनीतिक माहौल और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत अपनी रक्षा तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों के विस्तार पर काम कर रहा है, जिससे दक्षिण एशिया में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। SIPRI की रिपोर्ट ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में एशिया वैश्विक सामरिक और परमाणु शक्ति संतुलन का महत्वपूर्ण केंद्र बना रह सकता है।

वाराणसी आसानी से कनेक्ट उड़ानों के मॉडल में शामिल होने वाला पहला शहर: नागरिक उड्डयन मंत्री

नई दिल्ली/वाराणसी। देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि वाराणसी "ईजी कनेक्ट फ्लाइट्स मॉडल" में शामिल होने वाला देश का पहला शहर बनेगा।

इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को कम समय में

अधिक शहरों तक बेहतर हवाई संपर्क उपलब्ध कराना है। मंत्री के अनुसार, वाराणसी पहले से ही उत्तर भारत का एक प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र है। ऐसे में यहां से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने से न केवल यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और निवेश को भी नई गति मिलेगी। सरकार का लक्ष्य ऐसा नेटवर्क विकसित करना है, जिसमें यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा और जटिल ट्रांजिट प्रक्रियाओं से राहत मिले। वाराणसी को इस मॉडल के लिए चुनने के पीछे इसकी बढ़ती यात्री संख्या, रणनीतिक स्थिति और तेजी से विकसित हो रहा परिवहन ढांचा प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। शहर में रोपवे, एयरपोर्ट विस्तार और अन्य आधारभूत परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल रहता है तो इसे देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी लागू किया जा सकता है। इससे क्षेत्रीय हवाई सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और छोटे शहरों की देश के बड़े आर्थिक केंद्रों तक पहुंच आसान होगी। वाराणसी को देश की धार्मिक राजधानी और प्रमुख पर्यटन केंद्रों में गिना जाता है। बेहतर हवाई संपर्क से यहां आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है।